

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुमान-2

देहरादून: दिनांक: 22 जुलाई, 2013

विषय:- मैं 0 लामेर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राउलि0, नई दिल्ली को औद्योगिक प्रयोजन (स्टोन क्रेशर एवं स्टोन ग्रेड एण्ड सैण्ड) हेतु ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर में 3.547 हेठो भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-632/सात-स0भू030/2013 दिनांक-21.03.2013 एवं पत्र संख्या-867/सात-स0भू030/2013 दिनांक-15.05.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं 0 लामेर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राउलि0, नई दिल्ली को औद्योगिक प्रयोजन (स्टोन क्रेशर एवं स्टोन ग्रेड एण्ड सैण्ड) हेतु ग्राम ऊंचागांव, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर में आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अन्तर्गत 3.547 हेठो भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अहं होगा।

2- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (स्टोन क्रेशर एवं स्टोन ग्रेड एण्ड सैण्ड) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

3- जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4- जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूगिधर न हों।

5- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6- इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल स्टोन क्रेशर एवं स्टोन ग्रेड एण्ड सैण्ड के प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।

7- स्टोन क्रेशर स्थापित किये जाते समय स्टोन क्रेशर स्थापित किये जाने सम्बन्धी मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इकाई को स्टोन क्रेशर स्थापित किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में तत्समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

9- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भार/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

10- क्रय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्माण का प्लान सीड़ा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से रवीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11- इकाई को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12- आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

13- इकाई को विनियमित क्षेत्र के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

14- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

15- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

16- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कष्टा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

17- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- 18— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 19— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश, एवं इस शासनादेश के अनुपालन रिथति से भी शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृष्ठां- 2410 / समिनांकित / 2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— प्रगुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, देहरादून।
- 3— आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4— निदेशक, लामेर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राप्तिलो, उदय पार्क, नई दिल्ली।
- 5— निदेशक, एनोआई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावार सिंह चौहान)
अनुसचिव।